

ट्रम्प का ईरान के खिलाफ गैरकानूनी आक्रमण और उनके निष्कासन का आधार

क्या होता है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी र Nation के हितों की अवहेलना करता है, कानूनी दायित्वों को नजरअंदाज करता है, और वैश्विक आपदा को आमंत्रित करता है? यह निबंध 21 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरानी परमाणु सुविधाओं पर बमबारी को अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन के रूप में उजागर करता है, जो इजरायल के एजेंडे की सेवा करता है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाता है, और विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलता है। यह कानूनी और आर्थिक निहितार्थों को विस्तार से बताता है, दावा करता है कि ट्रम्प का सैन्य तैयारियों का आदेश देने के 48 घंटों के भीतर कांग्रेस को सूचित न करना उनके शपथ का विश्वासघात है, उनकी तत्काल निष्कासन की मांग करता है महाभियोग या 25वें संशोधन के माध्यम से, यूरोपीय राज्यों की मिलीभगत की निंदा करता है, ईरान की ऐतिहासिक शांतिप्रियता का उत्सव मनाता है, और माफी मांगने और संयुक्त राष्ट्र की जवाबदेही की मांग करता है।

ट्रम्प द्वारा अमेरिकी प्राथमिकताओं पर इजरायली हितों को प्राथमिकता देना

21 जून 2025 को ईरान के परमाणु स्थलों—फोर्डो, नटांज़, और इस्फहान—पर बमबारी करने का ट्रम्प का निर्णय इजरायल के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निष्क्रिय करने के लक्ष्य के साथ संरेखित है, जो अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक हितों की अवहेलना करता है। 13 जून 2025 को इजरायल के हमलों ने ईरान की प्रतिक्रिया को उकसाया, और ट्रम्प की तीव्रता, इजरायल के युद्ध में शामिल होने से, अमेरिका को एक ऐसे संघर्ष में उलझा देती है जिसमें कोई स्पष्ट लाभ नहीं है। केवल 25% अमेरिकी इन हमलों का समर्थन करते हैं, जो इस विदेशी उलझन की जनता द्वारा अस्वीकृति को दर्शाता है। इजरायल के एजेंडे की सेवा करके, ट्रम्प रूस, यमन, और पाकिस्तान की चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, जो अमेरिकी जीवन और संसाधनों को एक ऐसी वजह के लिए खतरे में डालता है जो राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करता है।

भूमध्यसागरीय शिपिंग मार्गों में व्यवधान से आर्थिक नुकसान

अमेरिकी हमले ने भूमध्यसागरीय शिपिंग मार्गों को अस्थिर कर दिया है, जो यूरोप और मध्य पूर्व के साथ अमेरिकी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकियों और यमन की लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनियों ने समुद्री जोखिमों को बढ़ा दिया है, जिससे इन मार्गों को अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है। यह व्यवधान शिपिंग लागतों में वृद्धि करता है, मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है, और व्यवसायों, विशेष रूप से स्थिर आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर छोटे उद्यमों, को खतरे में डालता है। आर्थिक नुकसान, ट्रम्प की आक्रामकता का प्रत्यक्ष परिणाम, विदेशी संघर्षों को अमेरिका की समुद्धि पर प्राथमिकता देता है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को स्व-प्रवृत्त नुकसान होता है।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का उल्लंघन करती है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी या आत्मरक्षा के बिना बल प्रयोग को निषिद्ध करता है। ईरानी खतरे के तत्काल होने का कोई सबूत नहीं है, और क्यूबा और चिली जैसे देशों ने इस हमले को गैरकानूनी के रूप में निंदा की है। परमाणु स्थलों को निशाना बनाना रेडियोधर्मी संदूषण और पारिस्थितिक नुकसान का जोखिम पैदा करता है, जिससे नागरिकों को खतरा होता है, हालांकि कोई बड़ा रिसाव दर्ज नहीं किया गया है।

घरेलू स्तर पर, ट्रम्प ने 1973 के युद्ध शक्ति संकल्प के तहत अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया, जो सशस्त्र बलों को शत्रुता या आसन्न शत्रुता में संलग्न करने के 48 घंटों के भीतर कांग्रेस को सूचित करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक कार्रवाइयाँ—14 जून 2025 को 00:00 UTC पर यूएसएस निमित्ज़ को आदेश देना, 15 जून 2025 को 00:00 UTC पर

टैंकर विमानों को, और 21 जून 2025 को 06:00 UTC पर बी-2 बमवर्षकों को—स्पष्ट रूप से हमले की योजनाओं को दर्शाती थीं, जिसके लिए प्रत्येक आदेश के 48 घंटों के भीतर अधिसूचना आवश्यक थी (उदाहरण के लिए, निमित्ज़ के लिए 16 जून 2025 को 00:00 UTC तक)। ट्रम्प का कांग्रेस को सूचित न करना, इन कार्रवाइयों के बावजूद जो 21 जून के हमले को संभव बनाती थीं, उनकी शपथ का विश्वासघात है, जैसा कि सीनेटर टिम केन और प्रतिनिधि अलेकजेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ जैसे सांसदों ने घोषित किया है, जो जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

वैश्विक शांति के लिए खतरा और तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम

ट्रम्प की आक्रामकता वैश्विक शांति को खतरे में डालती है, मध्य पूर्व को व्यापक संघर्ष की ओर धकेलती है जिसके वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। ईरान पर हमला करके, अमेरिका ने अनुच्छेद 51 के तहत ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार को सक्रिय कर दिया है, जिससे यमन, पाकिस्तान, और रूस इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। इन देशों की चेतावनियाँ अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एक गठबंधन के जोखिम को दर्शाती हैं, जिसमें रूस और चीन की भागीदारी संघर्ष को वैश्विक बना सकती है। परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम बी-2 बमवर्षकों की तैनाती गलत अनुमान के जोखिम को बढ़ाती है, जिससे मानवता तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुँच रही है। ट्रम्प का कूटनीति को अस्वीकार करना वैश्विक स्थिरता को कमजोर करता है, जिसके लिए इस खतरनाक रास्ते को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

ट्रम्प के निष्कासन की तत्काल आवश्यकता

ट्रम्प के गैरकानूनी कार्य और सैन्य तैयारियों के बारे में कांग्रेस को सूचित न करने की उनकी विफलता महाभियोग या 25वें संशोधन के माध्यम से उनकी तत्काल निष्कासन को उचित ठहराती है। युद्ध शक्ति अधिनियम के उल्लंघन और वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालने के कारण महाभियोग उचित है, जिसमें जवाबदेही के लिए द्विदलीय मांगें बढ़ रही हैं। 25वां संशोधन, जो उपराष्ट्रपति और कैबिनेट को ट्रम्प को अक्षम घोषित करने की अनुमति देता है, उनकी लापरवाही से इजरायल को अमेरिका से ऊपर रखने और कानूनी कर्तव्यों की अवहेलना के कारण व्यवहार्य है। सैन्य तैयारियों के आदेश देने के 48 घंटों के भीतर कांग्रेस को सूचित न करने की उनकी विफलता—14 से 21 जून के तैनाती में स्पष्ट—उनकी शपथ का विश्वासघात दर्शाती है, जिसके लिए और अधिक आपदा को रोकने के लिए त्वरित निष्कासन की आवश्यकता है।

यूरोपीय मिलीभगत की निंदा

स्पेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ग्रीस, जर्मनी, और इटली, जो RAF फेयरफोर्ड और रामस्टीन जैसे ठिकानों पर अमेरिकी टैंकर विमानों की मेजबानी करते हैं, इस गैरकानूनी आक्रमण में सहभागी हैं। ये विमान, जो 15 जून 2025 को 00:00 UTC पर तैनात किए गए थे, बी-2 बमवर्षकों के हमले को संभव बनाते थे, जिससे इन देशों को अनुच्छेद 2(4) के उल्लंघन में शामिल किया गया। उनकी तटस्थिता और अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने में विफलता निंदनीय है, जो उनकी शांति के समर्थकों के रूप में नैतिक स्थिति को कमजोर करती है। इन यूरोपीय राज्यों को वैश्विक स्थिरता को खतरे में डालने वाली युद्ध को सक्षम करने के लिए सबसे कठोर निंदा का सामना करना चाहिए।

ईरान की ऐतिहासिक शांतिप्रियता

ईरान सदियों से शांति का प्रतीक रहा है, जो सफाविद युग के बाद से आक्रामक युद्धों से बचता रहा है। 1979 के बाद इसकी संप्रभुता और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ प्रतिरोध पर ध्यान, जैसा कि ईरान-इराक युद्ध में देखा गया, रक्षात्मक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसकी IAEA द्वारा निगरानी की जाती है, शांतिपूर्ण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हथियारीकरण का कोई निश्चित सबूत नहीं है। अमेरिका और इजरायल के हमले एक ऐसी राष्ट्र पर अनुचित हमला हैं जिसने कूटनीतिक समाधान की तलाश की है, जो अपनी संयम और क्षेत्रीय योगदान के लिए सम्मान का हकदार है।

माफी और संयुक्त राष्ट्र जवाबदेही की मांग

इजरायल, अमेरिका, और सहभागी यूरोपीय राज्यों को अपने गैरकानूनी हमलों के लिए ईरान से औपचारिक माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने संप्रभुता का उल्लंघन किया और विनाशकारी नुकसान का जोखिम उठाया। अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो अधिकार को त्याग देना चाहिए, जो अक्सर स्वयं और इजरायल की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि हमले की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित हो सके। ऐसा प्रस्ताव, क्यूबा और चिली जैसे देशों द्वारा समर्थित, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि करेगा और अंतरराष्ट्रीय कानून में विश्वास बहाल करेगा, जो अक्टूबर 2023 में इजरायल-हमास संघर्ष की तीव्रता के बाद से कमज़ोर हुआ है।

निष्कर्ष

इजरायल के हितों की सेवा करने वाला ट्रम्प का ईरान पर गैरकानूनी हमला अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पंगु बना देता है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, और नागरिकों और पारिस्थितिकी को खतरे में डालता है। सैन्य तैयारियों का आदेश देने के 48 घंटों के भीतर कांग्रेस को सूचित न करने की उनकी विफलता उनकी शपथ का विश्वासघात है, जो वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है और तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम उठाता है। महाभियोग या 25वें संशोधन के माध्यम से उनकी तत्काल निष्कासन अनिवार्य है। यूरोपीय राज्यों की मिलीभगत स्पष्ट निंदा की मांग करती है। ऐतिहासिक रूप से शांतिप्रिय राष्ट्र ईरान माफी का हकदार है, और अमेरिका को जवाबदेही के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव की अनुमति देनी चाहिए। केवल इन कदमों के माध्यम से विश्व आपदा से बच सकता है और न्याय बहाल कर सकता है।